

राज्यपाल व मुख्यमंत्री “ एट होम ” में शामिल, 1 5 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक दिये

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी में कला व साहित्य की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया

उदयपुर, (कासं) 25 जनवरी। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शनिवार को “एट होम” कार्यक्रम में भाग लिया। इस

■ **राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जनजाति विकास मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, लोकसभा सांसद, स्थानीय विधायक व संभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।**

दौरान उन्होंने कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया।

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे शनिवार अपराह्न बाद सहेलियों की बाड़ी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी आगवानी की। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वन के साथ हुआ। इसके पश्चात राज्यपाल ने 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया।

पदक प्रदान किए तथा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए।

कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य

सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक उक्कल रंजन साहू, राज्यसभा सांसद चुन्रीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉ मन्नलाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण

विधायक फूलसिंह मीणा, वलूभनगर विधायक उदयलाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल आदि मौजूद थे।

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 25 जनवरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से यह जायकारी सामने आयी है। अमेरिका की एक अदालत ने मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी, जिससे राणा के भारत प्रत्यर्पित होने से बचने का आखिरी कानूनी मौका भी खत्म हो गया। यह रिट नवंबर 2024 में निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी,

जिसमें भारत में उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्टिओरीरी रिट एक कानूनी दस्तावेज है, जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है। राणा के भारत प्रत्यर्पण से मुंबई आतंकी हमलों के मामले में कई संवेदनशील खुलासे होने की उम्मीद है। 26/11 के आरोपी राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली का करीबी था, जिसने मुंबई में हमले की जगहों की रेकी भी की थी।

इस सप्ताह साठ वर्ष पूर्व चर्चिल की मृत्यु...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रूप में छवि बहुत बड़ी थी, और पाश्चात्य जगत के लोग उन्हें “स्वतंत्र विश्व” को बचाने वाले प्रचारित करते है लेकिन क्लैमेट एटली उस समय की जरूरतों को समझने में सक्षम था।

चर्चिल जब बहुत युवा थे तब ही से भारत के प्रति उनकी एक सोच विकसित हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिश काल में बतौर पत्रकार यहां काम किया। उन्होंने भारतीय सीमाओं पर लड़े गए कई युद्धों के बारे में लिखा। कोलकाता में उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की इसके बाद वे ब्रिटेन लौट गए।

जब चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ मित्र देशों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उस समय 1942 में बंगाल भी जब अकाल से जूझ रहा था और ये चर्चिल ही थे, जिन्होंने उस अकाल को भीषण त्रासदी में बदल दिया था क्योंकि उन्होंने बंगाल के लिए भेजे जा रहे अनाज के जहाजों को मित्र देशों की सेनाओं के लिए भेज दिया था और लाखों भारतीय भूख से मर गए थे।

कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान गिरा, रातों में फिर बढ़ी ठिठुरन

श्रीनगर, 25 जनवरी। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे रात में दोबारा ठिठुरन बढ़ गयी है। श्रीनगर स्थित मौसम केंद्र ने शनिवार को बताया कि कश्मीर घाटी में आज मौसम सुहावना और गर्म रहा। अगले चार दिनों में दिन के तापमान में धीरे-धीरे और महत्वपूर्ण वृद्धि होने, जबकि रात के तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं।

कश्मीर में 29 जनवरी को मौसम में बदलाव के आसार हैं, जिससे आसमान में बादल छाने और बारिश तथा बर्फबारी का अनुमान है। श्रीनगर में शुक्रवार देर रात के बीच तापमान शून्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया, जो सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

अनंतनाग जिले के पहलगाम और बारमुला के गुलमार्ग जैसे पर्यटक रिजॉर्ट में क्रमशः शून्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस और शून्य से नी डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान के साथ और भी ठंडी रातें दर्ज की गईं। कश्मीर में सर्दियों का सबसे कठोर चरण चिल्लाई-कल्ला, जो

■ **यह भी सोच अब पनप रही हैं कि जर्मनी पर, यहूदियों को “कन्सन्ट्रेशन कैम्प” आदि में की गई हत्याओं के कारण, “वार क्राइम्स” (युद्ध के अपराधों) के अंतर्गत मुकदमा चल सकता है, तो बंगाल में हुई भुखमरी के लिये चर्चिल व इंग्लैंड पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता।**

ऐसा नहीं था कि मित्र देशों की सेना भोजन के संकट से जूझ रही थी या उन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा था, चर्चिल ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कहीं मित्र देशों की सेनाओं को अकस्मात अनाज की जरूरत पड़ जाए। चर्चिल का वह युद्ध अपराध बहुत बड़ा था पर इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अकाल और भूख से मरने वाले लाखों भारतीय असहाय थे।

भारत के लिए 1942 बेहद कठिन समय था, जिसे चर्चिल ऐसा सुनहरा समय बता कर प्रचारित कर रहे थे जो हजारों सालों में एक बार आता है। यह समय है कि भारत को उन लोगों की याद में एक स्मारक बनाना चाहिए जो चर्चिल निर्णय (अन्यायपूर्ण निर्णय) की वजह

से भूख से मारे गए थे। जिस अनाज की उस समय भारतीयों को सखा जरूरत थी वह चर्चिल ने मित्र देशों की सेनाओं को दिलावा दिया।

युद्ध खत्म होने के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के युद्ध अपराधों पर विचार किया, जहां लाखों यहूदी व अन्य लोग यातना शिविरों व गैस चैम्बरों में मार डाले गए थे, पर उन्होंने भारत में भूख से मरे लाखों लोगों का कारण बने एक अपराध पर कभी भी विचार नहीं किया।

युद्धकाल में अगर चर्चिल को कोई व्यक्ति नापसंद था तो वह थे महात्मा गांधी जो चर्चिल एकदम विपरीत थे। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की “सिविलाइज्ड फोर्स” होने की धारणा को अस्वीकार कर दिया और चर्चिल को

यह अस्वीकृति कतई पसंद नहीं थी।

प्रशिक्षित सैनिक चर्चिल ब्रिटिश समाज के पारम्परिक समाज और रूढ़िवादी परम्पराओं साथ पले बढ़े थे। इसके विपरीत गांधी ने ताकत को अंतिम परीक्षण के रूप में नकार दिया था। गांधी की राजनीति चर्चिल को ख़ियोचित लगती थी। चरखा चलाने को चर्चिल औरतों का काम मानते थे।

क्लेमैंट एटली को श्रमिक नेता के रूप में चर्चिल ने उपप्रधानमंत्री बनाया था। एटली ने कई बार चर्चिल की सहायता की थी एटली एक जाने वाले वकील के बेटे थे वे 1920 के दशक में भारत आए थे और स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने खुद देखा था।

अगर 1947 में एटली ने भारत छोड़ने की प्रक्रिया तेज नहीं की होती तो भी भारत ब्रिटेन से आजादी छीन लेगा। भारतीय इतिहासकारों को सत्ता हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और इसमें एटली की भूमिका को विस्तार से देखना चाहिए। यह नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन करने का समय है।

ट्रम्प द्वारा चयनित नये...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि इससे आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी को और ज्यादा आधुनिक बनाने, परमाणु निरोध के प्रबंध, उभरते वैश्विक खतरों का मुकाबला करने और रणनीतिक रक्षा पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

डिफेंस सैक्रेटरी की भूमिका अमेरिकी प्रशासन में कितनी महत्वपूर्ण और गंभीर है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सैन्य कमान शृंखला में रक्षा सचिव राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। यहाँ तक कि सबसे उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को भी सैन्य संचालन करते समय रक्षा मंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं।

रक्षा सचिव वाइट हाउस और कांग्रेस के साथ मिलकर व्यापक विदेशी नीति के तह पहलों को विकसित करता है। सभी सैन्य विभाग एकीकृत होकर पेंटागन में एक एकल इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जो देश का सैन्य मुख्यालय है। रक्षा विभाग के मुख्य कार्यकारी के रूप में, रक्षा सचिव पेंटागन में सभी संचालन की निगरानी करते हैं।

इसके अतिरिक्त, चूंकि सशस्त्र सेवाएं केवल युद्ध नहीं करतीं, रक्षा विभाग में मजबूत खुफिया संचालन भी होते हैं और ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा

परिषद (एनएससी) को रिपोर्ट की जाती है। रक्षा सचिव इस खुफिया जानकारी को समन्वित करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा हैगसेथ महिलाओं के युद्ध में भाग लेने के खिलाफ बयान दे चुके हैं जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। सेना में स्त्री-पुरुष समानता पर उनके विचारों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। रिपोटर्स के अनुसार, नए रक्षा सचिव पर भारी शराब पीने और महिलाओं के प्रति आक्रामक व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें 2017 का एक यौन हमले का आरोप भी शामिल है, जिसे उन्होंने कोर्ट के बाहर निपटाय़ा।

कश्मीर में पहली वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल सम्पन्न

श्रीनगर, 25 जनवरी। शनिवार को कटरा में माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से मध्य कश्मीर तक पहली वंदे भारत ट्रेन के सफल परीक्षण के साथ कश्मीर के लिए ट्रेन का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना आखिरकार वास्तविकता के करीब है। उम्मीद है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने इस सेवा का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कश्मीर के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू हो जाएगी।

तुरंत प्रभाव से विदेशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीमो कहता है कि वर्तमान विदेशी सहायता के स्टॉप वर्क आर्डर तत्कालीन जारी हो जायेंगे तथा तब तक जारी रहेंगे, जब तक रुबियो समीक्षा नहीं कर लेता।

यूएस एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने, अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, “यह एक निर्मित दुर्व्यवस्था है।”

उक्त अधिकारी ने कहा, “सभी संस्थाओं को अपनी सारी गतिविधियाँ रोक देनी पड़ेंगी तथा इसी प्रकार सभी जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएँ, एचआईवी/एड्स, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सभी कृषि कार्य, शिक्षा तथा सिविल सोसायटी संगठनों की सारी सहायता रुक जायेगी।”

यूएसएआईडी के एक अधिकारी, जिन्होंने उनका नाम उजागर न करने का अनुरोध किया, ने कहा कि यूक्रेन में विभिन्न प्रोजेक्टों के जिम्मेदार अधिकारियों को सारा काम रोक देने के लिये कह दिया गया है। उस अधिकारी ने कहा कि रोक दिये गये प्रोजेक्टों में स्कूल तथा चिकित्सा सहायता, जैसे आपातकालीन मातृ-चिकित्सा तथा बच्चों के वैक्सिनेशन आदि शामिल हैं।

अगले 85 दिनों तक चलने वाली समीक्षा के बाद, क्या रुबिनो द्वारा निर्णय लिये जायेंगे कि ये सहायता कार्यक्रम जारी रहेंगे, संशोधित होंगे या रद्द कर दिये जायेंगे। उस समय तक, रुबियो ढील बरतने की स्वीकृति दे सकते हैं।

मीमो के अनुसार, रुबियोने आपातकालीन खाद्य सहायता के मामलों में भी ढील दे दी है। यह ढील गाज़ा स्ट्रिप में दी गई मानवीयता की खातिर दी गई है, जहाँ इज़रायल और फिलिस्तीनी उग्रवाधियों ने हमास में रविवार को युद्ध विराम की शुरुआत की थी। इसके अलावा, सूडान सहित, विश्व के अन्य कई भूख-पीड़ित क्षेत्रों में इस किस्म की ढील दी गई है।

स्टेट डिपार्टमेंट के मीमो में यह भी कहागया है कि रुबियो ने इन बूटों की स्वीकृति “इज़रायल तथा मिश्र के लिये विदेशी सैन्य वित्त-पोषण तथाउन प्रशासनिक खर्चों, जिनमें वेतन शामिल हैं, जो विदेशी सैन्य वित्त-पोषण के संचालन के लिये आवश्यक हैं।

फरिन मिलिट्री फायनेंसिंग के रूप में, इज़रायल को करीब 3.3 अरब डॉलर तथा मिश्र को करीब 1.3 अरब डॉलर मिलते हैं।

2025 में इस प्रकार की फायनेंसिंग के लिये चिन्हित किये गये अन्य देश हैं- यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलिपींस, थाईलैंड, ङ वियतनाम, डीजीबोती, कोलम्बिया, पनामा, इक्वेडोर, इज़रायल, मिश्र तथा जॉर्डन। इसके लिये पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन सरकार ने कांग्रेस से अनुरोध किया था।

इस अनुरोध में यह भी कहा गया था कि फरिन मिलिट्री फायनेंसिंग “लिबनान की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, ताकि वहाँ अस्थिरता को संभावना कम हो तथा ईरान के दुष्टभाव का प्रतिकार किया जा सके।” लिबनान की सेना इस समय देश के दक्षिण में तैनात होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इज़रायली सेनाएं युद्ध विराम समझौते के तहत वहाँ से हट रही हैं। इस समझौते के अनुसार, ईरान-समर्थक हिज़बुल्लाह हथियार और लड़ाकू भी उस क्षेत्र से हटाये जाने हैं।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गुजरात शामिल हैं, को लेकर भारी चिंता जताई जाती है, क्योंकि वहाँ शराब का बड़ा बाज़ार पनप रहा है, जहाँ प्रायः खतरनाक और मिलावटी शराब की बिक्री होती है। दूसरी तरफ, राज्य सरकारों को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है तथा इसे लागू करने पर सवाल खड़े होते रहे हैं तथा इसे लागू करने पर सवाल खड़े होते रहे हैं तथा भ्रष्टाचार तथा पुलिस-प्रताड़ना के आरोप भी लगते रहे हैं।

जहाँ बिहार जैसे राज्यों में

पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहाँ गुजरात विदेशियों तथा भारत के अन्य भागों से आये हुये लोगों को यह अनुमति देता है कि वे शराब खरीदने के लिये परमिट हेतु ऑनलाइन आवेदन करें तथा राज्य के 35 रजिस्टर्ड स्टोर्स में से किसी से भी शराब खरीद लें। नागालैंड में 1989 में शराब की बिक्री और उपभोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन रोक में ढील दी जा चुकी है तथा राज्य में “भारत निर्मित विदेशी शराब” खुले रूप में उपलब्ध बताई जाती है। कांग्रेस ने इस मद्द-निषेध नीति को “पूरी तरह विफल” बताया

है तथा कहा है कि इसे हटा लिया जाये।

आंध्र प्रदेश ने 1952 में शराबबंदी का प्रयोग किया था तथा उसके बाद एक बार 1994 में भी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने 1997 में इसे यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि सीमा पार से तथा राज्य के अंदर होने वाली लीकेज के कारण, शराबबंदी सफल और व्यवहार्य नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इससे पहले उमा भारती तथा शिवराज सिंह के कार्यकालों में शराबबंदी लागू करने की कोशिशें की जा चुकी है।

भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल की ओर से

सभी प्रदेशवासियों को

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

लखपति बनने का सपना साकार करें!

आपके लिए प्रस्तुत है

एसबीआई आवर्ती जमा योजना

» अकेले या संयुक्त रूप से खाता खोलें

अधिक जानकारी के लिए एसबीआई शाखा या Bank.sbi विजिट करें, 1800 1234 1 2100 पर कॉल करें

हमें यहाँ कॉल करें

अधिक जानकारी के लिए कृपया कोड जैक करें

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

76^{वें}

गणतंत्र दिवस

26 जनवरी

के पावन पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को

हार्दिक शुभकामनाएं

भारतीय संविधान देश की वैविध्यपूर्ण संस्कृतियों को एक सूत्र में मजबूती से जोड़ते हुए नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है।

आइए, इस गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पालन का संकल्प लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव को और सुदृढ़ बनाएं। साथ ही देश और प्रदेश की विकास यात्रा के पथगामी बनें।

भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान